



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, १ अप्रैल, १९८९/११ चैत्र, १९११

हिमाचल प्रदेश सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-२, ६ जनवरी, १९८९

संख्या ११-६/६७-गृह(ए)-ए-११.—हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या ११-६/६७-गृह(ए)-११, दिनांक २६-९-१९८८ जो कि राजपत्र, हिमाचल प्रदेश सरकार (असाधारण), दिनांक ४-१०-१९८८ के अंक में प्रकाशित हुई थी, के संदर्भ में तथा मैनोंवर फील्ड फायरिंग एवं आरटिलरी अभ्यास अधिनियम, १९३८ (१९३८ का पांचवा अधिनियम) की धारा ९ की उप-धारा (२) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जिला ऊना में हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना ११-६/६७-गृह(ए)-भाग-११, दिनांक ३-५-८८ जो कि राजपत्र (असाधारण), हिमाचल प्रदेश में १८ जून, १९८८ के अंक में प्रकाशित हुई थी के द्वारा पूर्व परिभाषित

क्षेत्र में फील्ड फायरिंग तथा आर्टिलरी अभ्यास को कार्यान्वित करने हेतु निम्नलिखित समय के लिए सहर्ष प्राधिकृत करते हैं :—

फरवरी, 1989	मार्च, 1989	अप्रैल, 1989	मई, 1989	जून,
2 से 4 तक	2 से 4 तक	3 से 5 तक	1 से 3 तक	1 से 3 तक
7 से 8 तक	7 से 8 तक	7 से 8 तक	5 से 6 तक	6 से 8 तक
10 से 11 तक	10 से 11 तक	10 से 11 तक	8 से 9 तक	12 से 14 तक
13 से 15 तक	13 से 14 तक	13 से 14 तक	11 से 12 तक	17 से 20 तक
17 से 18 तक	16 से 17 तक	17 से 18 तक	15 से 17 तक	22 से 24 तक
20 से 22 तक	27 से 28 तक	20 से 21 तक	19 से 20 तक	26 से 27 तक
24 से 25 तक	30 से 31 तक	24 से 25 तक	22 से 23 तक	29 से 30 तक
		27 से 28 तक	25 से 27 तक	
			29 से 30 तक	

आदेश द्वारा,
कंवर शमशेर सिंह,
आयुक्त एवं सचिव ।

भाषा एवं संस्कृति विभाग

शुद्धि-पत्र

शिमला-2, 18 जनवरी, 1989

संख्या भाषा-ई(3)-1/87.—इस विभाग की अधिसूचना संख्या भाषा-ई(3)-1/87, दिनांक 20-12-1988 की पंक्ति में प्रस्तावित शब्द “उप-मण्डलीय दण्डाधिकारी, बड़सर” के स्थान पर “उप-मण्डलीय दण्डाधिकारी, हमीरपुर” पढ़ा जाये ।

आदेश द्वारा,
महाराज कृष्ण काव,
वित्तायुक्त एवं सचिव ।

पर्यटन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 19 जनवरी, 1989

संख्या G-35/86-पर्यटन(सचि0).—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन नामतः गांव/मौजा सुलतानपुर, ह0 नं0 (18), परगना साच, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हैलीपैड के लिए पहुंच सड़क (अपरोच रोड) के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है । अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निदिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके में किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी ऐसा हितबद्ध व्यक्ति, जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के सम्मुख अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विस्तृत विवरण

जिला : चम्बा

तहसील : चम्बा

परगना	मौजा	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	
			बी०	बि०
साच	मुलतानपुर ह० नं० (18)	375/1	2	4
		389/1	2	9
		998/391/1	0	8
		1000/392/1/2	0	7
		399/1	0	11
		399/2	0	2
		कुल	4	1

आदेशानुसार,
ए० एन० विद्यार्थी,
वित्तियुक्त एवं सचिव।

परिवहन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 17 फरवरी, 1989

संख्या 6-56/81-परिवहन.—यतः राज्य सरकार का यह विचार है कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है।

2. अतः अब हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1972 की धारा 14(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजयोगा एंजुकेशन एण्ड रिसर्च फाऊंडेशन, नई दिल्ली की मोटर गाड़ियों नं० आर० टी० ए० 5158, आर० ए० डब्ल्यू 3694 और नं० आर० ए० जे० 4350 को कर क संदाय से सहर्ष छूट देते हैं।

जी० एस० चम्बियाल,
सचिव।

में बेलदार के पद पर कार्यरत थे, ने मस्ट्रोल पर अपनी हाजरियां दिनांक 23-10-85, 5-11-85, 18-11-85, 23-12-85, 6-1-86, 28-1-86, 15-2-86, 5-3-86, 21-3-86, 14-4-86, 28-4-86, 9-5-86, 26-5-86, 5-7-86, 28-8-86, 8-9-86, 11-9-86, 6-10-86, 21-10-86, 21-12-86, 21-1-87, 21-2-87, 21-3-87, 5-4-87, 5-5-87, 5-6-87, 24-6-87, 20-7-87 तथा 21-7-87 की लगाई जबकि इन्हीं दिनों को उक्त श्री जगत राम पंचायत बैठकों में तथा अन्य पंचायत कार्यों में उपस्थित था तथा उसने उपरोक्त दिनों की मजदूरी भी सिचाई विभाग से प्राप्त की है। उक्त श्री जगत राम पर पंचायत की पाईप चोरी करने का भी आरोप है ;

क्योंकि उपरोक्त आरोपों की वास्तविकता जानने के लिए जांच का करवाया जाना आवश्यक है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(2) के अन्तर्गत अतिरिक्त जिलाधीश, मण्डी को जांच अधिकारी नियुक्त करने का सहर्ष आदेश देते हैं वह अपनी जांच रिपोर्ट जिलाधीश, मण्डी के माध्यम से इस कार्यालय में भेजने की कृपा करें।

हस्ताक्षरित/-
अवर सचिव।

शिमला-2, 9 जनवरी, 1989

संख्या पी0सी0एच0एच0ए0(5)18/88.—क्योंकि श्री फतेह सिंह, प्रधान (नि0), ग्राम पंचायत अजौली, विकास खण्ड पांवटा, जिला मिरमौर के विरुद्ध पंचायत सभा निधि के 3530/- रुपये के दुरुपयोग के प्रयत्न का आरोप है। पंचायत घर की मुरम्मत का ठेका ग्राम पंचायत द्वारा श्री बलजीत सिंह को दिया गया तथा उक्त प्रधान ने मु0 6375/- रुपये का भुगतान उक्त ठेकेदार को किया जबकि विकास खण्ड पांवटा के कनिष्ठ अभियन्ता की असैसमेन्ट रिपोर्ट द्वारा पंचायत घर की मुरम्मत का कार्य केवल 2845/- रुपये का हुआ बताया है किन्तु उप-मण्डलाधिकारी (ना0), पांवटा की प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट तथा उक्त प्रधान को दिये गये नोटिस के फलस्वरूप उक्त ठेकेदार ने अधिक प्राप्ति की गई राशि दो किस्तों क्रमशः 3000/- व 530 रु0 वापिस पंचायत निधि में जमा कर दी। इस प्रकार उक्त प्रधान के विरुद्ध 3530/- रुपये की धन राशि पंचायत सचिव (सेवा निवृत्त) तथा ठेकेदार से मिली-भगत करके हड़प करने के प्रयत्न का आरोप है ;

और क्योंकि उपरोक्त तथ्य की वास्तविकता जानने के लिए जांच का करवाया जाना आवश्यक है।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत अतिरिक्त उपायुक्त, मिरमौर स्थित नाहन को जांच अधिकारी नियुक्त करने का सहर्ष आदेश देते हैं। वह अपनी जांच रिपोर्ट जिलाधीश मिरमौर के माध्यम से इस कार्यालय में प्रेषित करने की कृपा करेंगे।

हस्ताक्षरित/-
संयुक्त सचिव।

शिमला-2, 13 जनवरी, 1989

संख्या पी0सी0एच0एच0ए0(5)111/86.—क्योंकि श्री विनोद कुमार, पंच वार्ड नं0 3, ग्राम पंचायत निचला ग्रांड विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी को पंचायत बैठकों में भाग न लेने पर निष्कामनार्थ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था ;

और क्योंकि उक्त श्री विनोद कुमार पंच ने 6-12-88 से पंचायत बैठकों में भाग लेना शुरू कर दिया है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उक्त श्री विनोद कुमार के 6-12-88 से पंचायत की बैठकों में भाग लेने के तथ्य के दृष्टिगत उसके पिछले अनुपस्थितिकाल को दृष्टि अवगत करते हुए भविष्य में उसे सतर्क रहने का आदेश देते हैं। यदि भविष्य में किसी कारण वश वे पंचायत की बैठकों में भाग लेने में अयमर्थ हों तो इसकी सूचना उन्हें यथासमय पंचायत को देनी होगी।

शिमला-2, 3 फरवरी, 1989

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0(5) 180/77.—क्योंकि श्री रीपन लाल, प्रधान, ग्राम पंचायत रोहल, विकास खण्ड चौहारा के विरुद्ध यूको बैंक चड़गांव में ग्राम पंचायत का जाली प्रस्ताव प्रस्तुत करके 12-12-87 को पंचायत के वचत खाते से 1000/- रुपये की राशि निकालने का आरोप है;

और क्योंकि उक्त प्रधान को इस कृत्य के लिए सरकार द्वारा दिनांक 9 जून, 1988 को निलम्बनाथ कारण बताओ नोटिस दिया गया था किन्तु अपने उत्तर में उक्त आरोप को प्रधान ने मानने से इन्कार किया है;

और क्योंकि उपरोक्त आरोप की वास्तविकता जानने के लिए नियमित जांच का करवाया जाना जरूरी है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत जिला पंचायत अधिकारी, शिमला को जांच अधिकारी नियुक्त करने का सहर्ष आदेश देने हैं और साथ-2 यह भी आदेश देते हैं कि वे अपनी विस्तृत नियमित जांच रिपोर्ट एक माह के भीतर-2 जिलाधीश शिमला के माध्यम से इस विभाग को प्रेषित करेंगे।

शिमला-2, 9 फरवरी, 1989

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0(5) 47/88.—क्योंकि पंचायत दरकोटी ने अपने प्रस्ताव संख्या 5, दिनांक 12-4-88 द्वारा यह सूचित किया है कि श्री लयाकत अली उप-प्रधान, ग्राम पंचायत दरकोटी, विकास खण्ड जुब्बल-कोटखाई, जिला शिमला मास जनवरी, 1988 से पंचायत बैठक में अनुपस्थित रह रहे हैं;

क्योंकि उन्हें इसी कृत्य के लिए इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 18 अगस्त, 1988 को निलम्बनाथ कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था जिनका उत्तर भी उनसे प्राप्त नहीं हुआ है;

क्योंकि उपरोक्त तथ्य की वास्तविकता जानने के लिए जांच का करवाया जाना आवश्यक है।

अतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत उपसम्भागीय अधिकारी (आ0), रोहड़ू, जिला शिमला को जांच अधिकारी नियुक्त करने का सहर्ष आदेश देते हैं। वह अपनी जांच रिपोर्ट जिलाधीश शिमला के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित करने की कृपा करेंगे;

शिमला-2, 9 फरवरी, 1989

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0(5) 53/83.—क्योंकि ग्राम पंचायत सूलह, विकास खण्ड भवारना, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा ने अपने प्रस्ताव संख्या-111, दिनांक 9-11-87 द्वारा यह सूचित किया है कि श्री बलबीर सिंह,

उप-प्रधान, ग्राम पंचायत सुलह 31-8-87 से लगातार बिना पंचायत को सूचित किये पंचायत बैठकों से अनुपस्थित रह रहे हैं, जबकि पंचायत चौकीदार द्वारा उन्हें पंचायत की बैठकों की सूचना दी जाती रही है;

क्योंकि उप-प्रधान ग्राम पंचायत सुलह का यह कृत्य पंचायत की कार्यकुशलता में बाधक सिद्ध हो रहा है।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 जिसे ग्राम पंचायत नियमावली के नियम 77 के साथ पढ़ा जाता है श्री बलबीर सिंह, उप-प्रधान ग्राम पंचायत सुलह को निष्कासनार्थ कारण बताओ नोटिस देते हैं कि क्यों न उपरोक्त कृत्य के लिए उन्हें उनके पद से निष्कासित किया जाए उनका उत्तर इस नोटिस की प्राप्ति के एक मास के भीतर-2 जिलाधीश कांगड़ा के माध्यम से पहुंच जाना चाहिए अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

शिमला-2, 9 जनवरी, 1989

संख्या 0 पी 0 सी 0 एच 0-एच 0-एच 0 (5) 57/97.—क्योंकि श्री सुभाष चन्द प्रधान, ग्राम पंचायत दयाल ने ग्राम पंचायत की उस 2000/- रुपये की राशि का दुरुपयोग/अपहरण किया है जो ग्राम पंचायत ने श्री हरजिन्दर सिंह ठकदार से 26-6-86 को मछली तालाब की नीलामी के फलस्वरूप प्राप्त की थी।

क्योंकि उपरोक्त तथ्यों की वास्तविकता जानने के लिए जांच का करवाया जाना आवश्यक है।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत महायुक्त आयुक्त कांगड़ा को जांच अधिकारी नियुक्त करने का सहर्ष आदेश देते हैं। वह अपनी रिपोर्ट उपायुक्त कांगड़ा के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित करने की कृपा करेंगे।

शिमला-2, 23 फरवरी, 1989

संख्या पी 0 सी 0 एच 0-एच 0-एच 0 (5) 80/88.—क्योंकि ग्राम पंचायत गरहणा ने अपने पत्र संख्या 3/88, दिनांक 5-1-88 द्वारा सूचित किया है कि श्री रूप सिंह पंच, ग्राम पंचायत गरहणा, विकास खण्ड घुमारवीं जिला बिलासपुर 20-9-87 से लगातार अनुपस्थित रह रहे हैं। जिसकी पुष्टि खण्ड विकास अधिकारी, घुमारवीं व जिला पंचायत अधिकारी, बिलासपुर ने की है।

क्योंकि श्री रूप सिंह पंच का पंचायत की बैठकों से अनुपस्थित रहना पंचायत की कार्यकुशलता में बाधक सिद्ध हो रहा है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 जिसे ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 के साथ पढ़ा जाए श्री रूप सिंह पंच, ग्राम पंचायत गरहणा को निलम्बितार्थ कारण बताओ सूचना देते हैं कि क्यों न उपरोक्त कृत्य के लिए उन्हें उनके पद से निलम्बित किया जाये। उनका उत्तर इस नोटिस की प्राप्ति के एक माह के भीतर-2 जिलाधीश बिलासपुर के माध्यम से पहुंच जाना चाहिए अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

शिमला-2, 23 फरवरी, 1989

संख्या 0 पी 0 सी 0 एच 0-एच 0-एच 0 (5) 80/88.—क्योंकि ग्राम पंचायत गरहणा ने अपने पत्र संख्या 3/88, दिनांक 5-1-88 द्वारा सूचित किया है कि श्रीमती निर्मला देवी सह-विकल्पित महिला पंच लगभग 4 माह से पंचायत की बैठकों से अनुपस्थित रह रहा है जिसकी पुष्टि खण्ड विकास अधिकारी बिलासपुर ने की है;

क्योंकि श्रीमती निर्मला देवी सह-विकल्पित महिला पंच का यह कृत्य पंचायत की कार्यकुशलता में बाधक सिद्ध हो रहा है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 जिसे ग्राम पंचायत नियमावली, 1977 के नियम 77 के साथ पढ़ा जाए श्रीमती निर्मला दबी, सह-विकल्पित महिला पंच को निलम्बित कारण बताओ नोटिस देते हैं कि क्यों न उपरोक्त कृत्य के लिए उन्हें उनके पद से निलम्बित किया जाये। उनका उत्तर इस नोटिस की प्राप्ति के एक माह के भीतर-2 जिलाधीश बिलासपुर के माध्यम से इस कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

शिमला-2, 23 फरवरी, 1989

संख्या पी 0 सी 0 एच 0-एच 0 ए 0 (5) 51/86.—क्योंकि ग्राम पंचायत डीव, डाकघर ओडी, तहसील कुमारसेन, जिला शिमला ने अपने पत्र संख्या 13/88, दिनांक 19-11-88 द्वारा यह सूचित किया है कि श्री राकेश कुमार, पंच 8-12-86 से पंचायत की बैठकों में लगातार भाग नहीं ले रहे हैं। जिसकी पुष्टि खण्ड विकास अधिकारी, नारकण्डा ने भी की है ;

और क्योंकि श्री राकेश कुमार पंच का इस तरह पंचायत बैठकों से अनुपस्थित रहना पंचायत की कार्यवाही के प्रति उनकी उदासीनता का प्रतीक है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत जिसे ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 के साथ पढ़ा जाए, श्री राकेश कुमार, पंच, ग्राम पंचायत डीव को निलम्बित कारण बताओ नोटिस देते हैं कि क्यों न उपरोक्त कृत्य के लिए उन्हें उनके पद से निलम्बित किया जाए। उनका उत्तर इस कार्यालय में शीघ्र जिलाधीश शिमला के माध्यम से पहुंच जाना चाहिए अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

हस्ताक्षरित/-
अवर सचिव।

शिमला-171002, 4 मार्च, 1989

संख्या पी 0 सी 0 एच 0-एच 0 ए 0 (5) 44/83.—क्योंकि श्री ब्रह्मदास, प्रधान (निलम्बित), ग्राम पंचायत कार गुजागीर, विकास खण्ड नदौन, जिला हमीरपुर ने जिलाधीश द्वारा 24-1-1989 को जारी निलम्बन आदेशों को चुनौती दी है ;

और क्योंकि राज्य सरकार ने उक्त श्री ब्रह्मदास की प्रार्थना पर विचार करने के बाद निलम्बन आदेशों को समाप्त करने का निर्णय लिया है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(4) के अन्तर्गत जहां जिलाधीश, हमीरपुर के आदेश संख्या पंच एच 0-एच 0 आर-ग (4)-1/82-7078-81, दिनांक 24-1-89 को समाप्त करने का आदेश देते हैं वहां जिलाधीश के उक्त आदेशों में अंकित आरोपों को अतिरिक्त जिला-दण्डाधिकारी, हमीरपुर द्वारा जांच कराने का भी सहर्ष आदेश देते हैं।

हस्ताक्षरित/-
अनुपस्थित सचिव।

शिमला-2, 14 मार्च, 1989

संख्या पी.सी.एच.-एच.ए. (5) 42/77.—क्योंकि ग्राम पंचायत मायली ने अपने प्रस्ताव संख्या 3, दिनांक 20-6-88 द्वारा यह सूचित किया है कि श्री प्रेमलाल 11/87 से पंचायत बैठकों में अनुपस्थित रह रहे हैं जिसकी पुष्टि खण्ड विकास अधिकारी मशोबरा तथा जिला पंचायत अधिकारी शिमला ने की है।

क्योंकि उक्त पंच का यह कृत्य पंचायत की कार्यकुशलता में बिघन डाल रहा है तथा पंच का अपने कार्यों के प्रति उदासीनता का प्रतीक है।

अतः हिमाचल प्रदेश राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 जिसके पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 के साथ पढ़ा जाता है के अन्तर्गत श्री प्रम लाल, पंच का निलम्बित कारण बताओ नोटिस देते हैं कि क्यों न उपरोक्त कृत्य के लिए उन्हें उनके पद से निलम्बित किया जाय। उनका उत्तर इस नोटिस की प्राप्ति के एक माह के भीतर-2 जिलाधीश शिमला के माध्यम से पहुंच जाना चाहिए अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

शिमला-2, 14 मार्च, 1989

संख्या पी.सी.एच.-एच.ए.(5) 42/77.—क्योंकि ग्राम पंचायत मायली ने अपने प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 20-6-88 द्वारा यह सूचित किया है कि श्री सुखराम, पंच दिनांक 20-6-87 से पंचायत की बैठकों से अनुपस्थित रह रहे हैं जिसकी पुष्टि खण्ड विकास अधिकारी मशोबरा तथा जिला पंचायत अधिकारी शिमला ने की है ;

क्योंकि उक्त पंच का यह कृत्य पंचायत की कार्यकुशलता में बिघन डाल रहा है तथा पंच का अपने कार्यों के प्रति उदासीनता का प्रतीक है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत श्री सुखराम (पंच) को निलम्बित कारण बताओ नोटिस जिसे ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 के साथ पढ़ा जाता है के अन्तर्गत श्री सुख राम पंच को कारण बताओ नोटिस देते हैं कि क्यों न उपरोक्त कृत्य के लिए उन्हें उनके पद से निलम्बित किया जाये। उनका उत्तर इस नोटिस की प्राप्ति के एक माह के भीतर-2 जिलाधीश शिमला के माध्यम से पहुंच जाना चाहिए अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

शिमला-2, 14 मार्च, 1989

संख्या पी.सी.एच.-एच.ए.(5) 3/88.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 13 फरवरी, 1989 को इसलिए समाप्त करने का आदेश देते हैं क्योंकि श्री लक्ष्मण दास, प्रधान, ग्राम पंचायत भरमौर को उनके कथनानुसार अपना पक्ष प्रस्तुत करने का यथोचित अवसर नहीं मिला है।

इस आदेश का उक्त श्री लक्ष्मण दास के विरुद्ध चली जांच पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

हस्ताक्षरित/-
अवर सचिव।

शिमला-2, 14 मार्च, 1989

संख्या पी.सी.एच.-एच.ए.(5) 3/88.—क्योंकि उप-निदेशक, पंचायती राज, हिमाचल प्रदेश द्वारा 11/88 के दौरान किय गये ग्राम पंचायत भरमौर के निरीक्षण पर तथा भनकौता ग्राम निवासियों की शिकायतों पर निम्न-लिखित तथ्य सामने आये हैं जो श्री लक्ष्मण दास, प्रधान, ग्राम पंचायत भरमौर, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा की कार्य कुशलता के विरुद्ध जाते हैं ;

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 13 के अन्तर्गत माम में एक पंचायत बैठक का होना अनिवार्य है परन्तु 4/87 तथा 11/88 के बीच केवल तीन बैठकें हुई हैं। अतः स्पष्ट है कि इस प्रावधान की स्पष्ट उलंघना हो रही है जिसके लिए उचित स्थान का न होना कारण बनाया गया है जो अनुचित है क्योंकि स्थान की व्यवस्था करना भी प्रधान का कार्य है।

4/87 से 11/88 के बीच कोई भी बैठक ग्राम सभा की नहीं हुई जो उक्त अधिनियम की धारा 6 की स्पष्ट उलंघना है। ग्राम सभा की अनुमति तथा वजेट पाम हुए बगैर जो भी खर्च हुआ है वह अनियमित है।

अप्रैल 87 से नवम्बर, 1988 की अवधि में केवल अप्रैल, 88 व मई, 88 में किये गये व्यय पंचायत द्वारा पारित है। बाकी मार्गे व्यय अनियमित हैं जो कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) वित्त, वजेट लेखा आदि नियम, 1975 के नियम 6 की स्पष्ट उलंघना है।

भरमौर में बना पंचायत का विश्राम गृह घाटे में चल रहा है और उसके लिए मुख्यतः प्रतिदिन ठहरान की दर का 5/- रुपये होना तथा और कोई फालतु खर्च हो सकता है घाटे की इस बात को यदि कभी पंचायत के समुख रखा जात। तो पंचायत इसका समाधान ढूँढती।

शिक्षा विभाग के मलकाँता में स्थित प्राथमिक पाठशाला भवन को उनकी अनुमति लिए बगैर गिराना, भवन को गिराते समय प्राप्त सामग्री की सूची तैयार न करना तथा बाकी बची सामग्री को बेचने से प्राप्त धनराशि को सरकारी खजाने में जमा न करना एक ऐसा कृत्य है जो कि अवैध ही नहीं बल्कि पंचायत की गैर-जिम्मेदाराना प्रवृत्ति का सूचक भी है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 जिसे हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायती नियमावली, 1971 के नियम 77 के साथ पढ़ा जाये, श्री लक्ष्मण दास, प्रधान, ग्राम पंचायत-भरमौर को कारण बताओ नोटिस देते हैं कि क्यों न उपरोक्त कृत्य के लिए उन्हें उनके पद से निलम्बित किया जाये। उनका उत्तर इस नोटिस की जारी तारीख से एक माह के भीतर-2 जिलाधीश चम्बा के माध्यम से इस कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए अन्यथा उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

हस्ताक्षरित-
संयुक्त सचिव।

शिमला-171002, 14 मार्च, 1989

संख्या पी0सी0एच-एच0 ए (5) 42/77.—क्योंकि ग्राम पंचायत मायली ने अपने प्रस्ताव संख्या 3, दिनांक 20-6-1988 द्वारा यह सूचित किया है कि श्री कलौ राम, पंच, ग्राम पंचायत मायली दिनांक 20-2-1987 से पंचायत की बैठकों में अनुपस्थित रह रहे हैं जिसकी पुष्टि खण्ड विकास अधिकारी मणोहरा तथा जिला पंचायत अधिकारी शिमला न की है;

क्योंकि उक्त पंच का यह कृत्य पंचायत की कार्यकुशलता में गिरावट डाल रहा है तथा पंच का अपने कार्यों के प्रति उदासीनता का प्रतीक है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के प्रावर्त जिसे ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 के साथ पढ़ा जाता है, श्री कलौ राम पंच को निम्नकारण बताओ नोटिस देते हैं कि उपरोक्त कृत्य के लिए उन्हें उनके पद से निलम्बित किया जाए। उनका उत्तर इस नोटिस

की प्राप्ति के एक माह के भीतर-भीतर जिलाधीन शिमला के माध्यम से पहुंच जाना चाहिए अन्यथा एक तरफा कार्य-वाही अमल में लाई जाएगी।

शिमला-171002, 15 मार्च, 1989

संख्या पी0सी0एच-एच0ए (5) 196/77.—क्योंकि श्री प्रकाश चन्द, प्रधान (निलम्बित), ग्राम पंचायत जाहू, विकास खण्ड भीरंज, जिला हमीरपुर के विरुद्ध गवन/अनियमितताओं के निम्नलिखित आरोप सामने आये हैं :—

1. कि उसने दिनांक 22-4-1987 के बाद कोई भी व्यय पंचायत की बैठकों में पारित नहीं करवाया तथा ग्राम पंचायत की अनुमति बिना पशु मेला जाहू पर मु0 91412 रुपये व्यय किये तथा इस प्रकार हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) वित्त, बजट लेखा, अकॅक्षण कराधान सेवा तथा भत्ते नियम, 1975 के नियम 4 की उलंघना की है।
2. कि उसने बिना पंचायत के प्रस्ताव के पंजाब नेशनल बैंक जाहू तथा डाकघर जाहू से पंचायत के वचत लेखों से हजारों रुपये निकालकर व्यय किये तथा जाली प्रस्ताव पारित करके पंजाब नेशनल बैंक जाहू से 735/- रुपये प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 11-6-1988 द्वारा मु0 760.20 रुपये प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 6-7-1988 द्वारा तथा 3160/- रुपये की राशि प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 6-7-88 द्वारा निकाली है परन्तु पंचायत में ऐसे कोई प्रस्ताव उपलब्ध नहीं।
3. कि 24-4-1988 के प्रस्ताव संख्या 1 द्वारा कमेटी बनाकर यह पास किया गया है कि कमेटीयों की अनुमति लिये बिना मेले पर व्यय न किया जाये परन्तु प्रधान ने स्वेच्छापूर्वक 22532/- रुपये की राशि व्यय की है।
4. कि उसने पंजाब नेशनल बैंक जाहू से मु0 50,000/- रुपये की राशि प्राप्त करके बतौर ऋण बिना किसी स्वीकृति के जो कि हिमाचल प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1968 की धारा 45 की उलंघना की है।
5. कि 9/87 में हुए पशु मेला जाहू में श्री कालीदास एण्ड सन्ज जाहू से 517.40 रुपये का राशन इत्यादि सामान प्राप्त किया परन्तु इस दुकान से मु0 1736.15 रुपये की अदायगी का बिल प्राप्त करके प्रधान द्वारा 1218.75 रुपये अधिक व्यय रोकड़ में दर्ज करके इसका गवन किया।
6. कि उक्त प्रधान ने गनी निर्माण कार्य डोहरा से जाहू खुर्द का मस्ट्रोस मास 7/88 में 2320/- रुपये की बजाए 3170 रुपये रोकड़ में दर्ज किये हैं तथा इस प्रकार 850/- रुपये की राशि अधिक दर्ज की है।
7. 16-10-1986 को डाकघर जाहू के पंचायत वचत लेखा में 5000/- रुपये निकालकर 30-4-87 में रोकड़ में दर्ज किये तथा इस तरह मु0 5000/- रुपये की राशि छः मास से भी अधिक अवधि तक प्ररने पास रखी।
8. यह कि जांच के समय दिनांक 5-9-88 को उसके पास मु0 4153.63 रुपये की नकद शेष राशि थी, जिससे यह स्पष्ट है कि उसने हिमाचल प्रदेश सामान्य वित्त बजट लेखा अकॅक्षण कराधान सेवा भत्ता नियमावली, 1975 के नियम 8 की उलंघना की है।

9. पंजाब नैशनल बैंक जाहू से 11/87 में निकाली गई राशियां 4-6-88 के बाद गेकड़ में दर्ज की। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य वित्त, बजट, लेखा, अकेंक्षण, कराधान सेवा, भत्ता नियमावली, 1975 के नियम 9 की उलंघना की है।

10. कि पंचायत का स्टॉक भी सत्यापित नहीं किया गया तथा नकद बाकी भी प्रमाणित नहीं की जाती रही जो कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य वित्त, बजट, लेखा, अकेंक्षण, कराधान सेवा, तथा भत्ता नियमावली 1975 के नियम 10 की उलंघना है।

11. कि अकेंक्षण पत्र अवधि 4/86 से 3/87 की अनुपालना न करके हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य वित्त, बजट, लेखा, अकेंक्षण, कराधान सेवा तथा भत्ता नियमावली, 1975 के नियम 30 की उलंघना की है।

12. कि 10-6-1988 को हुई पंचायत की कार्यवाही पंचों की जानकारी के बिना पारित की तथा कार्यवाही पुस्तक में उपस्थित पंचों के हस्ताक्षर भी नहीं कराये और क्योंकि उपरोक्त तथ्यों की वास्तविकता जानने के लिए जांच का करवाया जाना अति आवश्यक है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत उप-संख्येलाधिकारी (ना०), हमीरपुर को जांच अधिकारी नियुक्त करने का सहर्ष आदेश देते हैं वह अपनी जांच रिपोर्ट उपायुक्त हमीरपुर की टिप्पणियों सहित शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करने की कृपा करेंगे।

शिमला-171002, 15 मार्च, 1989

संख्या पी०सी० एच०-एच० ए० (5)-26/77.—क्योंकि श्री हरनाम सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत करगानु, विकास खण्ड पच्छाद के विरुद्ध प्रारम्भिक जांच के फलस्वरूप निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आए हैं।

1. कि प्रधान श्री हरनाम सिंह ने धर्मासन का सभापतित्व करते हुए श्रीमती देवकू पत्नी श्री नरपत बनाम श्री केशवरां सुपुत्र श्री नराताराम के दिवानी दावे में श्री केशवरां के विरुद्ध 20/- रुपये हरजाना के लगाए तथा यह आदेश मौखिक होने के कारण सम्बन्धित मिसल में फैसला आदेश आज तक अनुलिखित है जिस कारण पंचायत सचिव फैसला आदेश की नकल देने में असमर्थ रहे तथा अपनी कर्तव्यपरायणता न निभा सकें।

2. कि उक्त प्रधान ने श्री रामस्वरूप से उसके पुत्र जयदत्त जिसका जन्म पंचायत रजिस्टर में दर्ज नहीं था के बाराहलफिया बयान देकर उसे स्वयं प्रमाणित किया तथा सचिव श्री लक्ष्मी सिंह पर दबाव डालकर प्रमाण-पत्र जारी करके जबकि सचिव ने उन्हें स्पष्ट शब्दों में यह बता दिया था कि न तो प्रधान हलफिया बयान प्रमाणित करने के सक्षम हैं तथा न ही वर्ष 1978 में हुए जन्म को दर्ज करने व प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु पंचायत सक्षम है परन्तु प्रधान ने यह कृत्य करके अपने पद का स्पष्टतया दुरुपयोग किया है।

3. कि प्रधान ने श्री सोमदत्त ग्राम बटोल की पुत्री कुमारी संगीता जिसका जन्म पंचायत रजिस्टर में दर्ज नहीं था, का प्रमाण-पत्र बिना रिकार्ड के जारी करके अपने पद का दुरुपयोग किया।

4. कि प्रधान द्वारा दो मोहरे (एक अपने घर सनोरा तथा दूसरी गिरिपुल में) रखी गई है तथा मई 1988 से अगस्त 1988 तक पंचायत बैठकों में अनुपस्थित रहें। प्रधान के इस कृत्य से जहाँ लोगों को प्रधान की मोहर की अनुपलब्धता के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ा। वहाँ पंचायत की कार्यकुशलता में भी काफी बाधा उत्पन्न होती रही। प्रधान का लगातार 4 बैठकों से अनुपस्थित रहना भी हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 की स्पष्ट उलंघना है।

5. कि उक्त प्रधान द्वारा सभा क्षेत्र में खोले गये पशु फाटकों को बन्द करवा दिया गया जबकि पंचायत सचिव ने इस तथ्य की पुष्टि की है कि ग्राम पंचायत के सदस्य व अन्य लोग प्रधान द्वारा पशु फाटक बन्द करने के विरोध में थे;

और क्योंकि उपरोक्त तथ्यों की वास्तविकता जानने के लिए जांच का करवाया जाना आवश्यक है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत उपमण्डलाधिकारी (ना0) राजगढ़ को जांच अधिकारी नियुक्त करने का सहर्ष आदेश देते हैं। वह अपनी जांच रिपोर्ट जिलाधीश, मिरमौर स्थित नाहन के माध्यम से शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करने की कृपा करें।

शिमला-171002, 15 मार्च, 1989

संख्या पी0 सी0 एच-एच0 ए0 (5) 22/85.—क्योंकि श्री अमर सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत कल्लर के विरुद्ध ग्राम सभा के कुछ सदस्यों द्वारा की गई शिकायत पर जिला अकेशन अधिकारी, बिलासपुर द्वारा की गई छानबीन के फलस्वरूप यह तथ्य सामने आया है कि उक्त प्रधान पंचायत की बैठकों में नियमित रूप से भाग नहीं ले रहे हैं परन्तु बैठकों के उपरान्त कार्यवाही रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर कर देते हैं।

2. कि उक्त प्रधान अक्सर रविवार व अन्य अवकाश वाले दिन पंचायत की बैठक बुलाते हैं जिससे पंचायत सदस्य सहमत नहीं है;

कि उक्त प्रधान हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में कानून के सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं तथा उन्होंने यह चुनाव लड़ने के लिए विश्वविद्यालय के नियमों की उल्लंघना करते हुए कानून के उपबन्धों के अनुसार कोई भी इजाजत नहीं ली।

3. कि प्रधान के 4-4-88 को कार्यवाही पुस्तिका पर ग्राम सभा की बैठक में हस्ताक्षर हैं परन्तु वास्तव में ग्राम सभा की कोई बैठक नहीं हुई है।

और क्योंकि प्रधान श्री अमर सिंह के यह उपरोक्त कृत्य पंचायत की कार्य कुशलता में बाधक सिद्ध हो रहे हैं तथा उपरोक्त तथ्यों की वास्तविकता जानने के लिए जांच का करवाया जाना आवश्यक है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत जहां श्री अमर सिंह प्रधान, ग्राम पंचायत कल्लर को निलम्बनार्थ कारण बताओ नोटिस जारी करते हैं कि क्यों न उन्हें उपरोक्त कृत्य के लिए उनके पद से निलम्बित किया जाए वहां तथ्यों की वास्तविकता जानने के लिए उप-मण्डलाधिकारी (ना0) बिलासपुर को जांच अधिकारी नियुक्त करने का सहर्ष आदेश देते हैं। वह अपनी जांच रिपोर्ट शीघ्र जिलाधीश बिलासपुर के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित करें तथा प्रधान ग्राम पंचायत कल्लर को यह भी आदेश देते हैं कि वह निलम्बनार्थ कारण बताओ नोटिस का उत्तर एक माह के भीतर-भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

हस्ताक्षरित/-
अमर सचिव।